भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 534 का उत्तर

तेलंगाना में रेलवे परियोजनाएँ

534. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए तेलंगाना में रेलवे परियोजनाओं के लिए कुल बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) तेलंगाना में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उन्नयन हेतु कितने रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं और उनके पुनर्विकास हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) काजीपेट में रेलवे विनिर्माण इकाई के पूर्ण होने की वर्तमान स्थिति/कुल केंद्रीय निवेश/संशोधित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व तट रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों में आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 35,045 करोड़ रुपए लागत की 2,165 किलोमीटर कुल लंबाई की 20 परियोजनाएं (6 नई लाइनें और 14 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से मार्च, 2025 तक 547 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 11,549 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च, 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर)	मार्च, 2025 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	6	840	245	4,611
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	14	1,326	303	6,939
कुल	42	2,165	547	11,549

तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए परिव्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	परिव्यय
2023-24	₹4,418 करोड़
2024-25	₹5,336 करोड़
2025-26	₹5,337 करोड़

वर्ष 2009-14 और 2014-25 के दौरान तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ की लंबाई	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	87 किलोमीटर	-
2014-25	774 किलोमीटर	8 गुना से अधिक

तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूरी हुई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)
1	पेद्दपल्ली- निज़ामाबाद नई लाइन (178 किलोमीटर)	926
2	जग्गय्यपेट-जनपहाड़ नई लाइन (48 किलोमीटर)	737
3	अक्कनपेट - मेडक नई लाइन (17 किलोमीटर)	205
4	भद्राचलम रोड-सत्तुपल्ली नई लाइन (56 किलोमीटर)	990
5	राघवपुरम-मंदमारि दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	165
6	रायचूर-गुंतकल दोहरीकरण (81 किलोमीटर)	388
7	सिकंदराबाद- महबूबनगर दोहरीकरण (85 किलोमीटर)	1,266
8	मल्टी-मोडाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमएमटीएस) चरण-II, हैदराबाद (103 किलोमीटर)	1,156
9	पेद्दपल्ली में बाईपास लाइन (2 किलोमीटर)	37

तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं जो हाल ही में शुरू की गई हैं, इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)
1	मनोहराबाद-कोत्तपल्ली नई लाइन (151 किलोमीटर)	2,781
2	मल्कानगिरी-पांडुरंगपुरम नई लाइन (174 किलोमीटर)	3,592
3	काज़ीपेट-विजयवाड़ा-तीसरी लाइन (220 किलोमीटर)	3,315
4	काजीपेट-बल्लारशाह-तीसरी लाइन (202 किलोमीटर)	3,183
5	गुंटूर- बीबीनगर दोहरीकरण (239 किलोमीटर)	2,853
6	मुदखेड़-मेडचल-डोन दोहरीकरण (417 किलोमीटर)	4,686
7	भद्राचलम रोड-डोर्नकल दोहरीकरण (55 किलोमीटर)	770
8	मोटूमारी-विष्णुपुरम दोहरीकरण और मोटूमारी पर आरओआर (100 किलोमीटर)	1,596
9	नष्कल (पिनडियाल)-हसनपर्ती रोड बाईपास (25 किलोमीटर)	465
10	सिकंदराबाद (सनथनगर)- वाडी तीसरी और चौथी लाइन (173 किलोमीटर)	5,012
11	डोर्नकल में रेल ओवर रेल (आरओआर) फ्लाईओवर (11 किलोमीटर)	327

पिछले 3 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) और चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2025-26 में, तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 5,672 किलोमीटर लंबाई के 57 सर्वेक्षण कार्य (18 नई लाइन और 39 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रुका हुआ है। तेलंगाना में भूमि अधिग्रहण की स्थिति इस प्रकार है:

कुल अपेक्षित भूमि	2,343 हैक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	1,580 हैक्टेयर (67%)
अधिग्रहण किए जाने हेतु शेष भूमि	764 हैक्टेयर (33%)

भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हैक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि (हैक्टेयर में)	अधिग्रहण किए जाने हेतु शेष भूमि (हैक्टेयर में)	राज्य को भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1.	गुंटुर-बीबीनगर दोहरीकरण	31	0	31	40
2.	मुदखेड़-मेडचल और महबूबनगर-डोन दोहरीकरण	70	0	70	30
3.	काजीपेट-विजयवाड़ा तीसरी लाइन	135	118	17	159
4.	मनोहराबाद - कोत्तपल्ली नई लाइन	1146	1050	96	-

तेलंगाना सरकार को मनोहराबाद - कोत्तपल्ली नई लाइन के लिए भूमि निःशुल्क प्रदान करनी होगी। मनोहराबाद से सिद्दीपेट तक 76 किलोमीटर पहले ही कमीशन की जा चुकी है। 151 किलोमीटर में से सिद्दीपेट - सिरिसिला (31 किलोमीटर) खंड जनवरी 2025 से लंबित है और इसे वित्त वर्ष

2025-26 में कमीशन करने का लक्ष्य है। बहरहाल, सिरिसिला के निकट 2.1 किलोमीटर वन भूमि डायवर्जन के लिए जनवरी 2025 में 10.10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन अब तक तेलंगाना सरकार द्वारा अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की गई है। इसलिए, सिद्दीपेट - सिरिसिला (31 किलोमीटर) की कमीशनिंग रुकी हुई है।

तेलंगाना में 04 परियोजनाओं, जिनकी कुल लागत 4,704 करोड़ रुपए है, को लागत भागीदारी आधार पर स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना सरकार की हिस्सेदारी 2,181 करोड़ रुपए है। तेलंगाना को इन लागत भागीदारी परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय में 1,708 करोड़ रुपए जमा करने थे। बहरहाल, उन्होंने केवल 894 करोड़ रुपए ही जमा किए हैं। इस प्रकार, 814 करोड़ रुपए की कमी है, जो कार्यों की प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनुमानित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

<u>स्टेशन पुनर्विकास</u>

भारतीय रेल ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों में सुधार करने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है। इस मास्टर योजना में निम्नानुसार शामिल हैं -

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार,
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण,
- स्टेशन भवन में सुधार,
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पानी के बूथ में सुधार,
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान,
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान,

- **प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर में सुधार/प्रावधान,**
- **'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान,**
- **पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों के साथ एकीकरण,**
- **दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं,**
- **बेहतर यात्री सूचना प्रणाली,**
- **प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग का प्रावधान आदि शामिल हैं।**

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 40 स्टेशन तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। तेलंगाना राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
तेलंगाना	40	आदिलाबाद, बसर, बेगमपेट, भद्राचलम रोड, गदवाल, हाफिजपेट, हाइ-टेक सिटी, हुप्पुगुडा, हैदराबाद, जदचेरला, जनगांव, काचीगुडा, कामरेड्डी, करीमनगर, काजीपेट जंक्शन, खम्मम, लिंगमपल्ली, मधिरा, महबूबाबाद, महबूबनगर, मलकपेट, मलकाजगिरी जं., मंचिरयाल, मेडक, मेडचल, मिरयालागुडा, नलगोंडा, निजामाबाद जं., पेद्दपल्ली जं., रामगुंडम, सिकंदराबाद, शादनगर, श्री बाला ब्रह्मेश्वर जोगुलम्बा, तंदूर, उमदानगर, विकाराबाद, वारंगल, यदाद्री, याकूतपुरा, जहीराबाद

तेलंगाना राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, इस योजना के अंतर्गत तेलंगाना राज्य में 03 स्टेशनों (बेगमपेट, करीमनगर, वारंगल) के चरण-I के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं तथा कुछ स्टेशनों पर कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:

- **बासर स्टेशन: प्लेटफार्म की सतह और प्लेटफार्म की दीवार के सुधार के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। परिचलन क्षेत्र, प्लेटफार्म शेल्टर और प्रतीक्षालय में सुधार के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

- **खम्मम स्टेशन: प्लेटफॉर्म शेल्टर, सामान्य प्रतीक्षालय, विश्रामालय और वातानुकूलित लाउंज में सुधार के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। पैदल पार पुल, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ी, स्टेशन भवन और परिचलन क्षेत्र के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

- **श्री बाला ब्रह्मेश्वर जोगुलांबा स्टेशन: प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करने, प्लेटफार्म विस्तार, स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र, प्लेटफार्म शेल्टर और दिव्यांगजन सुविधाओं में सुधार के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। फिनिशिंग कार्य शुरू कर दिया गया है।**

- **हाफिजपेट स्टेशन: स्टेशन भवन, बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय और शौचालय के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह, परिचलन क्षेत्र, संकेतकों, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ी, 12 मीटर पैदल पार पुल और दिव्यांगजन सुविधाओं के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

- **काजीपेट जंक्शन स्टेशन: प्लेटफॉर्म शेल्टर, मौजूदा सामान्य प्रतीक्षालय का सुधार, शौचालय, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ी के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। स्टेशन भवन, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र और पैदल पार पुल के सुधार के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत् और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की

उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार कार्य शुरू किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्यों को स्वीकृति देने और निष्पादन के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ एवं उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः, इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार या राज्य-वार। तेलंगाना राज्य दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस जोन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 863 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक (अक्टूबर, 2025 तक) 664.27 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

काज़ीपेट में विनिर्माण इकाई

भारतीय रेल ने तेलंगाना के काज़ीपेट में 521.36 करोड़ रुपए की लागत से एक रेल निर्माण इकाई विकसित करने की योजना बनाई है, जो विभिन्न आधुनिक चल स्टॉक के विनिर्माण और अनुरक्षण में सक्षम होगी। इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, सिविल और विद्युत अवसंरचना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अधिकांश मशीनरी और संयंत्र संस्थापित कर दिए गए हैं।

*****